Difficulties in application in under-developed Countries

Fagan महोदय के अनुसार ~~[illegible]~~ त्याग सिद्धान्त को अर्द्धविकसित देशों में लागू करना कठिन है क्योंकि ये सिद्धान्त अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है जो निम्नलिखित है —

(1) प्रगतिशील कर का सम्बन्ध निम्नतम जीवन निर्वाह आय के स्तर से ऊपर के आय से माना गया है।

(2) मौद्रिक आय के वृद्धि के साथ साथ सीमान्त उपयोगिता मुद्रा की घटती जाती है।

(3) प्रत्येक करदाता के मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता ह्रास की रेखा का आकार एक समान होता है।

(4) सार्वजनिक व्यय का आय के सीमान्त उपयोगिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

वास्तविक जीवन में ये मान्यताएँ लागू नहीं होते हैं। अर्द्धविकसित देशों में सार्वजनिक व्यय से अधिक आर्थिक विकास प्रभावित होती है। वस्तु की तरह आय की ह्रासमान सीमान्त उपयोगिता प्रत्येक करदाता को प्राप्त करना कठिन है। इसलिए Fagan ने निष्कर्ष निकाला है — "If however, these assumptions are removed none of the sacrifice theories will logically infer progressive taxation."

The Faculty theory — प्रगतिशील कर के subjective approach (त्याग) की सीमाओं को देखते हुए seligman ने प्रगतिशील कर के लिए objective view of ability को अपनाने को कहते है। Faculty theory के अनुसार अधिक आय, धन सम्पति तथा उपभोग पर ऊँचे दर से करारोपण किया जाना चाहिए और यह प्रगतिशील कर का उचित ढाँचा देता है।

Difficulties — अर्द्धविकसित देशों में कुछ ही लोगों के हाथ में अधिक आय का स्रोत होता है और वे कर की चोरी में अधिक विश्वास करते है

The surplus income theory — J. A. Hobson ने अपने 'Taxation in the New state' में लिखा है — The ability of the tax payer to bear a tax depends on his 'surplus income.'

Hobson ने surplus income को परिभाषित करते हुए लिखा है —

"Surplus income those elements of income which do not dry up under taxation and the taxing of which does not distrub industry."

Hobson के अनुसार surplus income से ही बचत होता है किन्तु over-saving या under-consumption के कारण व्यापार चक्र का जन्म होता है। इसलिए प्रगतिशील कर को लागू कर व्यापार चक्र की समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है।

Difficulties — अर्द्धविकसित देशों में Hobson का surplus theory लागू करना कठिन है। व्यापार चक्र की समस्या विकसित देशों की समस्या है। अर्द्धविकसित देशों में गरीबी का दुष्चक्र की समस्या रहती है और अधिकांशतः आय से अधिक व्यय की समस्या रहती है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने भी under-consumption को एक मात्र व्यापार चक्र का कारण मानने से इनकार किया है।

The Social Importance theory

Sir Sydney Chapman ने ethical postulate के आधार पर प्रगतिशील कर को लागू किया है। इनके अनुसार प्रारम्भ में प्राप्त आय से बहुत अधिक आवश्यकताएं संतुष्ट होती है तथा इसका सामाजिक महत्व है किन्तु बाद में आय वृद्धि से Extra wants की पूर्ति

का समाज में ~~अब~~ उतना महत्व नहीं होता है।
इसलिए Chapman लिखते हैं — Considering the normative value of wants satisfaction, it is desirable that primary wants need not be taxed at a higher rate in order to maintain equity ~~of~~ in taxation.

इस प्रकार करभार का न्यायोचित वितरण की समस्या Psychological नहीं है वरन् Ethical है।

Difficulties — अर्द्धविकसित देशों में इसे लागू करना कठिन है क्योंकि ~~आय~~ आय के दर तथा Moral या social importance के बीच सम्बन्ध स्थापित करना व्यवहार में सम्भव नहीं है। इस नीति के आधार पर प्रगतिशील कर लागू नहीं किया जा सकता है।

The Sociopolitical Theories

Taussing के अनुसार "The question of equity in taxation can not be discussed independently of the equity of the whole existing (socio-political) order."

समाज के सामाजिक तथा राजनीतिक नियामों

के संदर्भ में तथा सामाजिक कल्याण को ध्यान देते हुए प्रगतिशील कर को लागू किया जाना चाहिए न कि व्यक्तिगत त्याग को आधार बनाना चाहिए।

<u>Difficulties</u> - सामाजिक तथा राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रगतिशील कर को लागू करना कठिन हो जाता है। Fagan ने लिखा है — "Proportional taxation will cause the least disturbance to the status quo."

इसलिए प्रगतिशील कर की अपेक्षा आनुपातिक कर लगाया जाना चाहिए। क्योंकि Socio-political theory के अनुसार समाज में सर्वप्रथम "Objective criteria of social welfare" स्थापित किया जाना चाहिए और इस उद्देश्य की प्राप्ति में अगर प्रगतिशील कर सहायक हो तो इसे लागू ~~किया~~ जाना चाहिए अन्यथा नहीं।

इस प्रकार उपर्युक्त सभी सिद्धान्तों ~~के~~ ने प्रगतिशील कर को लागू करने की सलाह तो देते हैं किन्तु अर्द्धविकसित देशों में इसे लागू करना कठिन है।

Sandhya Rani
Deptt of Economics